साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 100 | जौनपुर, शनिवार, 30 नवम्बर 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

धर्म के मामलों में फंसना ठीक नहीं : संभल हिंसा पर गुलाम नबी आजाद

नई दिल्ली,(एजेंसी)। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि धर्म से जुड़े मामलों में फंसना देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है। जम्मू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आजाद ने धार्मिक ध्रुवीकरण के खतरों के बारे में लोगों को आगाह किया। आजाद ने संभल हिंसा पर किए गए सवाल के जवाब में कहा, ''धर्म के मामले में उलझना ठीक नहीं है। यह देश की एकता और अखंडता के साथ–साथ समाज के लिए भी सही नहीं है।'' उन्होंने इस तरह की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए आगाह किया कि इससे समुदायों में विभाजन बढ़ेगा तथा शांति भंग होगी। संभल जिले के कोट गर्वी क्षेत्र में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर पिछले रविवार को हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई तथा पुलिसकर्मियों सहित कई अन्य घायल हो गए। अदालत के आदेश के बाद ही मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था।

अनियंत्रित गाड़ी तालाब में पलटने से चार की मौत, तीन घायल

बिहार (एजेंसी)। अरवल जिले के कलेर प्रखंड में कामता गांव से बारातियों को लेकर पटना जा रही एक गाड़ी के बृहस्पतिवार को अनियंत्रित होकर एक तालाब में पलटने से वाहन सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। थाना प्रभारी मोहम्मद अली साबरी ने बताया कि प्रसादी इंग्लिश मुहल्ला के पास एक वाहन तालाब में पलट गया जिससे एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित चार लोगों की मौत हो गई एवं तीन अन्य व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शवों को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इस हादसे में जख्मी तीन अन्य घायलों का प्रारंभिक उपचार सदर अस्पताल किया गया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता व्यक्त की

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव के बीच , कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आध्यात्मिक गुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद पड़ोसी देश की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश मामलों की समिति ने 11 दिसंबर को बांग्लादेश की स्थिति पर एक बैठक बुलाई है। समिति का नेतृत्व वर्तमान में सांसद शशि थरूर कर रहे हैं । .. अगर सरकार को विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ कहना है, तो यह अच्छा होगा कि (विदेश मंत्री) एस जयशंकर संसद में आएं और हमें बताएं।

उपचुनाव में भाजपा की जीत से विपक्ष भयभीत, 2027 में इससे भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे : सीएम योगी

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में विजयी नवनिर्वाचित विधायकों के अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों को उपचुनाव के दौरान मिले दायित्वों को लेकर की गई कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि टीम भावना और एकजुटता के साथ कार्य करने से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत से विपक्षी दल भयभीत हो गये हैं। वो अब बस आरोप ही लगा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी को आश्वस्त किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा इससे भी बड़ी जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व में एनडीए ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, महाराष्ट्र में भारी बहुमत हासिल किया और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर विजय प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने चुनाव से पहले ही सात सीटें जीतने की रणनीति बनाई थी, जिसे संगठन और कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतारकर सफल बनाया। योगी ने कुंदरकी और कटेहरी जैसी कठिन सीटों पर जीत को पार्टी की रणनीति और कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि जहां लोग जीत की संभावना पर सवाल उठाते थे, वहां भाजपा ने न केवल जीत हासिल की बल्कि अपनी स्थिति और मजबूत की। कुंदरकी में 1.45 लाख वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने पार्टी की विचारधारा और कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण पर जोर देते हुए कहा कि भाजपा हर चुनौती को अवसर में बदलने का माद्दा रखती है। उन्होंने सातों विधानसभा में मिली जीत को कार्यकर्ताओं और नेताओं के मजबूत प्रयास का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए यह जीत विपक्ष के मन में भय उत्पन्न करेगी। हमें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा और सघन जनसंपर्क के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर शाह, नड्डा के साथ 'सकारात्मक' चर्चा हुई

मुंबई,(एजेंसी)। रवाना होने से पहले यहां संवाददाताओं से बातचीत में शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला राज्य की राजधानी में महायुति गठबंधन की एक अन्य बैठक में लिया जाएगा। शिंदे ने निवर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ बृहस्पतिवार देर रात शाह तथा नड्डा से मुलाकात की तथा महाराष्ट्र में अगली सरकार के लिए सत्ता साझेदारी सहमति पर बातचीत की। विधानसभा चुनावों में भाजपा नीत गठबंधन को प्रचंड

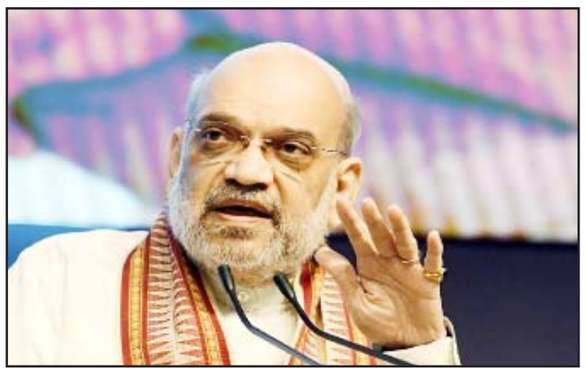

बहुमत मिलने के बाद यह बैठक हुई। शिंदे ने शुक्रवार सुबह संवाददाताओं से कहा, ''बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। यह पहली बैठक थी। मुंबई में महायुति की एक और बैठक होगी।

प्रियंका गांधी ने विपक्षी सदस्यों के साथ दिखाई एकजुटता

केरल ,(एजेंसी)। वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने सदन में तब प्रवेश किया जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी सदस्य संभल हिंसा और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रियंका गांधी उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी सीट के पास खड़ी रहीं। विरोध के बीच उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों से मुलाकात भी की और उनका अभिवादन किया। जैसे ही वह अन्य सदस्यों से मिलने के लिए विपक्षी खेमे की अग्रिम पंक्ति के करीब गईं द्रमुक सांसद कनिमोई को उन्हें अपने साथ बैठने का इशारा करते देखा गया। प्रियंका ने कुछ देर कनिमोई से बातचीत के बाद अन्य सदस्यों का अभिवादन किया। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्यों के साथ बातचीत करते देखा गया।

अगर पीएम वहां बिरयानी खाने जा सकते हैं.., भारत–पाकिस्तान क्रिकेट विवाद में कूदे तेजस्वी यादव

नई दिल्ली,(एजेंसी)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि भारतीय टीम को अगले साल आईसीसी चौंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा करनी चाहिए और अपने रुख का समर्थन करते हुए दावा किया कि खेलों में राजनीति को शामिल करना अच्छी बात नहीं है। चौंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की पाकिस्तान यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, टूर्नामेंट शुरू होने में बस कुछ ही महीने बाकी हैं। तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण, भारत ने 2008 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है, जब उन्होंने एशिया कप में भाग लिया था। दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वियों ने आखिरी बार 2012–13 में भारत में द्विपक्षीय श्रृंखला खेली थी, जिसमें सफेद गेंद के मैच शामिल थे। वर्तमान में, वे मुख्य रूप से आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप में एक–दूसरे का सामना करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात पर जोर दिया कि बोर्ड भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। भारत ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने का रुख दृढ़ता से रखा है। तेजस्वी ने

पत्रकारों से कहा कि खेल में राजनीति को शामिल करना अच्छी बात नहीं है. क्या हर कोई ओलंपिक में भाग नहीं लेता? भारत को वहां (पाकिस्तान) क्यों नहीं जाना चाहिए? आपत्ति क्या है? अगर प्रधानमंत्री वहां बिरयानी खाने जा सकते हैं – तो अच्छा है, अगर भारत की टीम यात्रा करती है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बोर्ड अंतिम निर्णय लेने से पहले शुक्रवार को बैठक के दौरान आम सहमति पर पहुंचने का लक्ष्य रखेगा। टूर्नामेंट 19 फरवरी से मार्च के बीच होने वाला है, लेकिन आईसीसी ने अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है।

हिन्दुओं की सुरक्षा करे बांग्लादेश सरकार, लोकसभा में बोले एस जयशंकर, हम चिंतित, मामले को गंभीरता से ले रहे

नई दिल्ली,(एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जयशंकर ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बारे में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने अगस्त 2024 से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की कई रिपोर्टें देखी हैं, जब शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जयशंकर ने कहा कि सरकार ने पूरे बांग्लादेश में अगस्त 2024 के महीने सहित हिंदुओं और अन्य

अल्पसंख्यकों, उनके घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और मंदिरोंध्धार्मिक स्थानों पर हमलों की कई रिपोर्टें देखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। बांग्लादेश में हाल ही में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मंदिरों और पूजा मंडपों पर हमलों की खबरें भी सामने आईं। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने दुर्गा पूजा 2024 के दौरान ढाका के तांतीबाजार में एक पूजा मंडप पर हमले और सतखिरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी के संबंध में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इन हमलों के बाद, बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण उत्सव को सुनिश्चित करने के लिए सेना और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की तैनाती सहित विशेष सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति पर कड़ी निगरानी रखता है। अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है।

वक्फ बिल मुसलमानों पर हमला, ममता का केंद्र पर निशाना, बोलीं- राजनीतिक कारणों से इसे लाया गया

नई दिल्ली,(एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे पर हमला है। उन्होंने दावा किया कि यह बिल मुसलमानों के अधिकार छीन लेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस बिल पर हमसे सलाह नहीं ली। यह बिल मुसलमानों पर हमला है और हम इसका समर्थन नहीं करते। हम इसका विरोध करेंगे। गैर–मुसलमानों सहित विभिन्न समुदाय वक्फ संपत्तियों के लिए दान देते हैं और धन का उपयोग कल्याण और विकासात्मक कार्यों, जैसे स्कूल स्थापित करना, घर

बनाना, छात्रवृत्ति देना आदि के लिए किया जाता है। ममता ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ विधेयक से मुसलमानों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है (बिल) राजनीतिक कारणों से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी धर्म पर हमला हुआ तो वह पूरे दिल से इसकी निंदा करेंगी। विपक्षी दलों ने मौजूदा वक्फ अधिनियम में विधेयक द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की कड़ी आलोचना की है तथा आरोप लगाया है कि ये संशोधन मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया है कि संशोधन से वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और वे जवाबदेह बनेंगे। इस विवादास्पद विधेयक की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ मामलों को ब्रिटिश काल में 1934 में एक अधिनियम के तहत लाया गया था और आजादी के बाद इसमें संशोधन किया गया तथा 1995 में एक और संशोधन किया गया था।

सांसदों और संसद को लेकर चिंतित है जनता, चाहती है सदन चले : बिरला

नई दिल्ली,(एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच शुक्रवार को कहा कि देश की जनता सांसदों एवं संसद के बारे में चिंतित है तथा वह चाहती है कि सदन की कार्यवाही चले। उन्होंने यह टिप्पणी प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों से सदन की बैठक चलने देने की अपील करते हुए की। बिरला ने इस दौरान नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा, ''देश की जनता चाहती है कि सदन चले। कई माननीय विद्वानों ने लिखा है कि संसद चलनी चाहिए, चर्चा–संवाद होना चाहिए। सहमति और

असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है।'' उनका कहना था, 'मैं आग्रह करता हूं कि जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार, आप सदन चलाने में सहयोग करें। आज स्वास्थ्य एवं महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है।'' उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता सांसदों और संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है ।

बिहार सरकार ने भूमि संबंधी अनियमितताओं के लिए 180 अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है : मंत्री

बिहार,(एजेंसी)। सरकार ने अनियमितताओं की शिकायत परराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 180 अंचल अधिकारियों (सीओ) के खिलाफ कार्रवाई की है और लगभग 139 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। जायसवाल भाजपा विधायक पवन कुमार जायसवाल द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके स्थानीय भू–माफियाओं के साथ मिलीभगत करके पूर्वी चंपारण जिले के दो सरकारी स्कूलों पुलवरिया और पचपकड़ी की जमीन बेच दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जायसवाल ने कहा, मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजग सरकार विभाग के किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को नहीं बख्शेगी। विभाग ने भ्रष्ट आचरण में लिप्त 180 सीओ के खिलाफ कार्रवाई की है।'' उन्होंने कहा,'' इसके अलावा 139 सीओ के वेतन पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि उन्होंने विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया।

शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन भी विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली,(एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी गतिरोध जारी रहा। दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामा के वजह से आज की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। इसका मतलब साफ है कि शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में संसद के दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पहले सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया। अब सोमवार 2 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा सदन पहुंची और विपक्षी सदस्यों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हुईं। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक शुक्रवार को एक बार के स्थगन के बाद पुनरू शुरू होने के करीब 10 मिनट के अंदर दोपहर बारह बजकर 10 मिनट पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस सदस्य अदाणी समूह से जुड़े मामले को उठा रहे थे, वहीं सपा सांसद संभल हिंसा का मुद्दा उठाते देखे

गए। हंगामे के बीच ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच शुक्रवार को कहा कि देश की जनता सांसदों एवं संसद के बारे में चिंतित है तथा वह चाहती है कि सदन की कार्यवाही चले। उन्होंने यह टिप्पणी प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों से सदन की बैठक चलने देने की अपील करते हुए । की। बिरला ने इस दौरान नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा, ''देश की जनता चाहती है कि सदन चले। कई माननीय विद्वानों ने लिखा है कि संसद चलनी चाहिए, ।

संपादकीय

प्रियंका की दृष्टिकोण

केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा की 4.1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हुई भारी जीत कांग्रेस पार्टी के लिये एक उत्साहजनक संदेश है। निश्चित रूप से उनके राजनीतिक जीवन और कांग्रेस पार्टी के लिये यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। शायद यह पहली बार है कि संसद में गांधी परिवार के तीन लोग सदस्य हैं। उनसे पहले राज्यसभा में मां सोनिया गांधी और लोकसभा में भाई राहुल गांधी की सक्रिय उपस्थिति बनी हुई है। उनकी इस जीत से निश्चित रूप से संसद में गांधी परिवार के प्रभाव को मजबूती मिलेगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह आज भी वंशवादी नेतृत्व पर पार्टी की निर्भरता को रेखांकित करता है। निस्संदेह, प्रियंका गांधी अपने आकर्षक व्यक्तित्व व प्रभावी कुशल वक्ता के रूप में पहचान रखती हैं। वह कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य की बड़ी उम्मीद हैं। उनकी उपस्थिति पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करती है। एक ओर जहां राहुल गांधी के नेतृत्व व अभिव्यक्ति को लेकर आलोचना की जाती रही है, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने नपे–तुले शब्दों में मुद्दों को तार्किक ढंग से उठाने के लिये भी जानी जाती हैं। उनका यह राजनीतिक कौशल वायनाड में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बखूबी देखा गया। अपने इसी गुण के चलते वह चुनाव अभियान के दौरान तमाम मतदाताओं, खासकर महिलाओं के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में कामयाब रहीं। लोगों को साथ जोड़ने की यही क्षमता उनकी निर्णायक जीत में खासी मददगार साबित भी हुई। उनके चुनाव अभियान ने कार्यकर्ताओं में नये उत्साह का संचार किया। यही वजह है कि पार्टी के भीतर उनकी सफलता को लेकर खासा जोश भी है। पार्टी के भीतर भी कई लोगों को उम्मीद है कि उनकी इस रिकॉर्ड जीत से कांग्रेस पार्टी संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो सकेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो देश में पार्टी की अपील में आशातीत विस्तार की संभावनाओं को बल मिल सकेगा। फलतरू पार्टी को मौजूदा संकट से उबरने में मदद मिलेगी। यह निर्विवाद सत्य है कि राजनीतिक समय की दृष्टि से प्रियंका गांधी वाड्रा की सफलता के खास मायने हैं। उनकी संसद में दस्तक ऐसे समय में हुई जब देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रही है। पार्टी को हाल के दिनों में महत्वपूर्ण चुनावी झटकों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में सत्ता की चाबी पार्टी के हाथ से फिसलकर भाजपा की झोली में जा गिरी है। राजनीतिक पंडित इन असफलताओं को पार्टी की घटती प्रासंगिकता के रूप में देखते रहे हैं। साथ ही कहा जाता है कि पार्टी भाजपा की संगठनात्मक ताकत को चुनौती दे पाने में विफल रही है। दूसरे शब्दों में, पार्टी भाजपा के राजनीतिक विमर्श का विकल्प नहीं दे पा रही है। साथ ही यह अहम सवाल भी उठाया जा रहा है कि सक्रिय राजनीति में प्रियंका का उदय क्या संघर्षरत कांग्रेस में नई जान फूंक सकने में कामयाब होगा? दरअसल, वायनाड में उनकी जीत को स्थानीय सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर दमदार उपस्थिति के लिये उन्हें अभी और मेहनत करनी होगी। इस जीत को राष्ट्रीय गति में बदलने के लिये रणनीतिक सुधारों, गठबंधनों और भविष्य के लिये स्पष्ट दृष्टिकोण की जरूरत होगी। अभी यह देखना बाकी है कि क्या भविष्य के लिये वे एक स्पष्ट दृष्टिकोण का लाभ पार्टी का जनाधार विकसित करने के लिये दे पाएंगी। या फिर वह कांग्रेस की वंशवादी राजनीति की निरंतरता के रूप में उभरती हैं। निस्संदेह, जैसे ही वह राष्ट्रीय सुर्खियों में कदम रखेंगी, उन्हें पार्टी में नई प्राणवायु का संचार करने के लिये कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें कालांतर यह भी साबित करना होगा कि कांग्रेस मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एक व्यवहार्य विकल्प पेश कर सकती है। बहरहाल, प्रियंका गांधी वाड्रा की वायनाड में हुई शानदार जीत से न केवल केरल बल्कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई आशा का संचार हुआ है।

भारतीय राजनीति वास्तव में वृद्धों का क्षेत्र

भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की संख्या 20: हो जाने की उम्मीद है। भारतीय संसद, जैसे कि संकेत पर, पहले से ही 'ग्रेइंग जोन' जैसी दिखने लगी है। कुछ अनुमान बताते हैं कि चुने गए सांसदों में से सिर्फ 10प्रतिशत ही 25–40 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं। संसद के सदनों, केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की औसत आयु भी ग्रेइंग जोन से बहुत दूर होने की संभावना नहीं है। विडंबना यह है कि बुजुर्गों के नेतृत्व वाला देश अक्सर युवाओं से भरा देश होने के लिए अपनी पीठ थपथपाता है। दुख की बात है कि यह जनसांख्यिकीय लाभांश सत्ता के गलियारों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। भारतीय राजनीति में बुजुर्गों के लिए एक वास्तविक ब्रह्मांड होने के कई कारण हैं। स्वभाव से, भारत एक ऐसा देश लगता है जो अक्सर गलत तरीके से उम्र को समझदारी से जोड़ता है। इसी तर्क से, युवा नेताओं को उतावलेपन और अनुभवहीनता का प्रतीक माना जाता है। परिणामस्वरूप, भारतीयों को, पिछले कुछ वर्षों में, पुरुषों और कभी–कभी महिलाओं द्वारा चुने जाने और उनका नेतृत्व करने में कोई परेशानी नहीं हुई है, जिनके सिर पर थोड़े से सफेद बाल हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि युवा यह भी पाते हैं कि राजनीतिक दलों में ऊपर की ओर बढ़ने की सीढ़ी पर बुजुर्गों की भीड़ है। इससे युवाओं के लिए प्रभावशाली पद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, चाहे वह राजनीतिक संगठन हो या संस्थान। भारतीय राजनीति के युवा न होने का एक और प्रासंगिक कारण युवाओं की राजनीति के प्रति उदासीनता है। यह अनुचित नहीं है। युवाओं के एक बड़े हिस्से को राजनीति छल–कपट और अन्य प्रकार की अनैतिकता का क्षेत्र लगती है। इसलिए उनके लिए सार्वजनिक जीवन में करियर बनाना सबसे अच्छा नहीं है। राजनीति के पुराने लोमड़ी के मैदान होने के निहितार्थ, जैसा कि यह था, गंभीर हैं। पर्याप्त संख्या में युवा नेताओं की अनुपस्थिति राजनीतिक कक्षों द्वारा भारत के युवाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की अनदेखी करने की संभावना को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, युवाओं का अधिक प्रतिनिधित्व निस्संदेह देश में कम से कम दो ज्वलंत समस्याओं – युवा बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन पर अधिक गंभीर और जोशीली बहस का कारण बनता। शायद अब समय आ गया है कि भारत की राजनीतिक पार्टियाँ अपने युवा नेताओं को कम उम्र से ही अधिक जिम्मेदारियाँ सौंपें ताकि वे सत्ता की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो सकें। बैकबेंच युवा राजनेताओं के लिए जगह नहीं है।

पीएम बार्नियर को जीवित रहने के लिए ले पेन की जरूरत है?

इस वर्ष यूरोपीय संसद के चुनावों में, मरीन ले पेन के नेतृत्व में फ्रांस की दूर–दराज राष्ट्रीय रैली (त्छ) ने उम्मीद के मुताबिक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, जो अब ष्बृहस्पतिष की तरह नहीं रह गए हैं, ने अचानक संसदीय चुनाव कराने का फैसला किया, यह जानते हुए कि बजट घाटा सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत से अधिक होगा, और वे अपने आव्रजन और पेंशन सुधारों के माध्यम से फ्रांस को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कोई भी कार्यक्रम लागू करने में असमर्थ होंगे। 7 जुलाई को, विधायी चुनाव के परिणामस्वरूप केंद्र, वाम और चरम वामपंथियों को त्छ का मुकाबला करने के लिए एक अवसरवादी गठबंधन में सफलता मिली। ग्रीन्स, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और जीन–ल्यूक मेलेनचॉन के नेतृत्व में चरम वामपंथियों वाली वामपंथी पार्टियों ने 37 वर्षीय कम्युनिस्ट लूसी कास्टेट्स को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए 289 वोटों की आवश्यकता होती है, जो एक बहुत ही खंडित संसद में हासिल करना बहुत मुश्किल है। कैस्टेट्स के अलावा सरकार के नेता के लिए मैक्रोन के किसी भी विकल्प को वोट से खारिज करने की धमकी देकर, मेलेनचॉन ने प्रभावी रूप से पहल ले पेन को सौंप दी। ` बिना लगभग 60 दिनों के बाद, मैक्रोन को 5 सितंबर को गॉलिस्ट रूढ़िवादी लेस रिपब्लिकन (एलआर) से 73 वर्षीय पूर्व चार बार मंत्री रहे मिशेल बार्नियर को नियुक्त करके ले पेन को टालना पड़ा, जिसने केवल 47 सीटें हासिल कीं, लोगों को एक साथ लाने के लिए बार्नियर के अनुभव पर भरोसा किया। बार्नियर को 235 सीटें मिलने की उम्मीद थी, जिसमें मैक्रोन का गठबंधन 166, 47 एलआर वोट और 22 का मध्यमार्गी कैच–ऑल समूह था, लेकिन 289 की जरूरत से कम था। ले पेन की आरएन चुनाव में केवल तीसरे स्थान पर आने से निराश थी, लेकिन फिर भी बार्नियर की नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, और क्योंकि संविधान 12 महीने के लिए संसद को भंग करने की अनुमति नहीं देता है, ले पेन अगले साल जून में एक और संसदीय चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं। ले पेन की अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए एक बाधा यह है कि वह एक दशक पुराने न्यायालय मामले में फंसी हुई हैं, जिसमें उन पर यूरोपीय आयोग से अपने और 24 सहयोगियों के लिए झूठे बहाने से धन लेने के लिए ईपी में अपने सहकर्मियों की संख्या में हेराफेरी करने का आरोप है। उनके लिए सबसे बुरा परिणाम कम से कम पांच साल के लिए सार्वजनिक पद लेने पर प्रतिबंध हो सकता है। सुनवाई 1 अक्टूबर से शुरू हुई और इसमें कई सप्ताह लगेंगे। 1 अक्टूबर को ही, बार्नियर ने अपनी नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उनका उद्देश्य ष्संवाद और समझौता की संस्कृति को सरकार का सिद्धांत बनानाष था। यह मैक्रोन की शासन शैली की निहित आलोचना है, जिसे अवास्तविक और कृपालु दोनों माना जाता है। उन्होंने अगले साल की शुरुआत में संसद के साथ सहायता प्राप्त मृत्यु और उपशामक देखभाल पर बातचीत फिर से शुरू करने का वादा किया है, और नियमित आधार पर आम जनता के साथ परामर्श चाहते हैं। बार्नियर ने घाटे को अगले साल जीडीपी के पांच प्रतिशत और 2029 में तीन प्रतिशत तक कम करने का अपना लक्ष्य घोषित किया, जिसमें कम खर्च से भारी कटौती की जाएगी। उन्होंने इस साल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी का हवाला देते हुए सबूत दिया कि फ्रांस पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रभावी हो सकता है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने व्यापक विरोध के बावजूद सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने के लिए कानून पारित किया था, जिसके कारण सड़कों पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। बार्नियर ने कहा कि वे पेंशन प्रणाली और पेंशन कानून में उचित बदलावों पर यूनियनों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने 1 नवंबर से न्यूनतम वेतन में दो प्रतिशत की वृद्धि की और सख्त आव्रजन नीतियों का वादा किया। अल्पमत सरकार के प्रमुख के रूप में, बार्नियर को 8 अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने ले पेन के आरएन की मदद से पार कर लिया, जिसने तब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री की तत्परता की प्रशंसा की। अब 2025 के लिए उनके पहले बजट को पारित करने की बाधा है। उनका मसौदा 10 अक्टूबर को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन नए वित्त और बजट मंत्रालयों के पास प्रस्तावों को तैयार करने के लिए बहुत कम समय था और कई को केवल मोटे तौर पर बताया गया है। घाटे में कटौती वाला बजट बार्नियर की टिकने की शक्ति का एक बड़ा परीक्षण हैय प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, उनका मसौदा एक संतुलनकारी कार्य है और यह देखना बाकी है कि करों और खर्च में कटौती संसदीय बहस में टिक पाती है या नहीं। सबसे अधिक संभावना है कि बजट पारित होने से पहले महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। फ्रांस के बजट वाद–विवादों ने पहले भी अविश्वास प्रस्ताव को जन्म दिया है और बार्नियर की योजनाओं ने इसके विवरण ज्ञात होने से पहले ही विरोध को जन्म दिया है। एक दूर–वामपंथी सांसद ने कहा, ष्यह इस देश में अब तक देखी गई सबसे हिंसक मितव्ययिता योजना है, इससे फ्रांसीसी लोगों को नुकसान होगाष। घाटे और बढ़ते कर्ज को नियंत्रण में लाने के लिए यूरोपीय आयोग के दबाव में बार्नियर ने कहा कि यह खर्च में कटौती और उच्च आय वालों और बड़ी कंपनियों पर कर वृद्धि के माध्यम से फ्रांस की बजटीय स्थिति में 60 बिलियन यूरो का सुधार करेगा। अधिकांश कटौती सरकारी खर्च पर केंद्रित है, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है। फ्रांस अब स्पेन की तुलना में अधिक ऋण प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, और इटली और ग्रीस से मांगे गए उच्च जोखिम वाले प्रतिफल के करीब पहुंच रहा है, बार्नियर के पास बहुत कम गुंजाइश है। ले पेन ने कहा है कि वह बार्नियर के बजट का समर्थन तभी करेंगी जब वह खरीद मूल्य में वृद्धि करेंगे। फ्रांसीसी नागरिकों की शक्ति का उपयोग करना। यदि विपक्षी दल एक साथ बजट मसौदे का विरोध करते हैं, तो सरकार के पास एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग करके मतदान के बिना इसे पारित करने का विकल्प है, जो बिल को तब स्वीकृत मान लेता है जब इसे सांसदों के बहुमत द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन यह अविश्वास के दूसरे वोट का रास्ता तैयार करता है, जिससे बार्नियर का अस्तित्व फिर से ले पेन और उनकी दूर–दराज की राजनीति के हाथों में चला जाता है। मैक्रोन के पास अन्य विकल्प हैं, जिनमें से कोई भी आकर्षक नहीं हैय उसी प्रधानमंत्री को फिर से नियुक्त करना, एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना, इस्तीफा देना (जिसे उन्होंने पहले खारिज कर दिया है) या जनमत संग्रह कराना। अब जबकि जर्मनी राजनीतिक रूप से बिखरता हुआ दिख रहा है, यूरोप का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देश फ्रांस भी उसी दिशा में बढ़ रहा है।

नागा शांति वार्ता : गाँठ खोलना मुश्किल हो सकता है

ऐतिहासिक युद्ध विराम के सत्ताईस साल बाद और 600 दौर की वार्ता के बाद, विद्रोही नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक–मुइवा) या एनएससीएन (आई–एम) और भारत सरकार के बीच शांति वार्ता लगभग निर्णायक बिंदु पर पहुंच गई है। पहले नागा विद्रोही समूह नागा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) की तरह एनएससीएन (आई–एम) ने भी संप्रभु नागा मातृभूमि हासिल करने के लिए हथियार उठाए। बाद में, 1 अगस्त, 1997 के युद्धविराम के बाद नई दिल्ली के साथ शुरू हुई वार्ता के दौरान, एनएससीएन (आई–एम) ने स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर एक समाधान पर पहुंचने पर सहमति व्यक्त की। विद्रोही संगठन ने हमेशा कहा कि वह अपनी गरिमा और सम्मान से समझौता नहीं करेगा और नागाओं के लिए एक अलग झंडा और संविधान (येझाबो) चाहता है। एनएससीएन (आई–एम) की इन दो मांगों पर चुप रहने या कुछ भी ठोस नहीं कहने के बाद, जिसे संगठन ने समय के साथ अपना ष्मुख्य मुद्दाष कहा, भारत सरकार ने आखिरकार नागाओं के लिए एक अलग झंडा और संविधान के लिए मना कर दिया। इस लेखक ने हाल के सप्ताहों में जिन दो वरिष्ठ नगा राजनीतिक नेताओं से बात की, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कहा कि केंद्र एनएससीएन (आई–एम) की इन दो मांगों में से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता। नगालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एस.सी. जमीर ने अमित शाह के हवाले से कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जहां केवल एक झंडा, एक संविधान और एक प्रधानमंत्री हो सकता है। नगालैंड के उपमुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और दूसरे उपमुख्यमंत्री वाई. पैटन के साथ श्री शाह से मुलाकात की थी, ने भी केंद्रीय गृह मंत्री के हवाले से श्री जमीर द्वारा कही गई बातों के समान ही बातें कही। एस.सी. जमीर, जो एक पूर्व राज्यपाल भी हैं, द्वारा नई दिल्ली में श्री शाह से मुलाकात के एक दिन बाद, एनएससीएन (आई–एम) ने हाल के वर्षों में सबसे आक्रामक बयान दिया, जिसमें उसने अपने सशस्त्र संघर्ष को फिर से शुरू करने और भारत के खिलाफ हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध का सहारा लेने की धमकी दी, ताकि वह "नगालिम" या नगा मातृभूमि के अद्वितीय इतिहास और संप्रभु अस्तित्व की रक्षा कर सके। एनएससीएन (आई–एम) के महासचिव थुइंगलेंग मुइवा, जो एटो किलोंसर या ष्प्रधान मंत्रीष भी हैं, द्वारा 7 नवंबर को जारी किए गए एक लंबे पांच–पृष्ठ के बयान में, एनएससीएन (आई–एम) नेता ने कहा कि भारत सरकार अब एक राजनीतिक समझौता थोप सकती है जो 3 अगस्त, 2015 के फ्रेमवर्क समझौते का अक्षरशः सम्मान और आदर नहीं करेगा। फ्रेमवर्क समझौते पर भारत सरकार और एनएससीएन (आई–एम) ने काफी धूमधाम से हस्ताक्षर किए थे और यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री मुइवा की उपस्थिति में हुआ था और माना जाता है कि इसी के आधार पर अंतिम नागा शांति समझौता होना था। वृद्धों का क्षेत्र 1997 के युद्धविराम के बाद से नई दिल्ली के साथ अपने सबसे सीधे टकराव में, एनएससीएन (आई–एम) के महासचिव ने कहा कि अगर भारत और जिसे वे ष्नागालिमष कहते हैं, के बीच कोई हिंसक टकराव होता है, तो यह 2015 के फ्रेमवर्क समझौते का सम्मान नहीं करने के कारण होगा। श्री मुइवा ने अपने वक्तव्य में एक बार फिर स्पष्ट किया कि सम्मानजनक राजनीतिक समाधान की उम्मीद तभी की जा सकती है जब भारत सरकार किसी भी राजनीतिक समझौते में "नागालिम" के लिए एक संप्रभु ध्वज और संविधान को आधिकारिक रूप से मान्यता दे और स्वीकार करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनएससीएन (आई–एम) के महासचिव ने यह भी कहा कि उनका समूह यह सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का प्रस्ताव करना चाहेगा कि 2015 के फ्रेमवर्क समझौते का अधिकारियों द्वारा अक्षरशः सम्मान किया जाए। श्री मुइवा ने यह भी कहा कि यदि केंद्र द्वारा इस तरह की राजनीतिक पहल को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एनएससीएन (आई–एम) "नागालिम" की संप्रभुता, स्वतंत्रता और इसके अनूठे इतिहास की रक्षा के लिए हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध फिर से शुरू करेगा। स्पष्ट रूप से, इसे एनएससीएन (आई–एम) द्वारा पिछले 27 वर्षों से जारी संघर्ष विराम को समाप्त करने की धमकी के रूप में देखा जा सकता है। एनएससीएन (आई–एम) की धमकी और अलग ध्वज और संविधान के खिलाफ नई दिल्ली के दृढ़ रुख ने नागा शांति प्रक्रिया को फिर से शुरुआती बिंदु पर ला खड़ा किया है। आखिरकार, अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू–कश्मीर में हुए बड़े बदलावों के बाद, नई दिल्ली देश में कहीं भी अलग झंडे जैसे प्रतीकों पर रियायत देने की स्थिति में नहीं है। कई सवाल उठते हैं। साथ गतिरोध खत्म नहीं हो सकता है, तो क्या भारत सरकार आगे बढ़कर विद्रोही समूहों के समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेगी, जो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स या छछच्ळे के नाम से जाने जाते हैं? छैब्छ की तरह जिसने 2015 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, छछच्ळ ने 2017 में सहमत पदों पर हस्ताक्षर किए। अब, छछच्ळ का मानना घ्घ्है कि जहां तक घ्घ्समूह का सवाल है, भारत सरकार के साथ बातचीत खत्म हो गई है और वह शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एनएससीएन (आई–एम) जैसे प्रमुख हितधारक के बिना हस्ताक्षरित नागा शांति समझौता नागा क्षेत्रों में स्थायी शांति ला सकता है क्योंकि वहां का समाज विभाजित है जिसमें कुछ वर्ग एनएससीएन (आई–एम) का समर्थन करते हैं और अन्य एनएनपीजी का समर्थन करते हैं। फिर से, पूछा जाने वाला सवाल यह है कि किस ताकत के बल पर एनएससीएन (आई–एम) नेता हथियार उठाने और जिसे वह ष्सशस्त्रीकरणष कहता है उसे फिर से शुरू करने की धमकी दे रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि छैब्छ(प्–ड) नई दिल्ली के साथ बातचीत करते हुए भी फिर से सशस्त्र संघर्ष छेड़ने की तैयारी कर रहा है? क्या यह संभव है कि वार्ता विफल होने की स्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए पहले से ही लड़ाकों के एक बड़े समूह को जंगलों में भेज दिया हो? क्या यह संभव है कि यांमार और चीन के तत्वों का समर्थन प्राप्त है, ये दो ऐसे देश हैं जहाँ इसके कैडरों की अतीत में आसान पहुँच थी? बेशक, ऐसे लोग भी हैं जो यह मानना घ्घ्चाहेंगे कि करीब तीन दशकों तक सामान्य नागरिकों की तरह आरामदायक स्थिति में रहने के बाद, छैब्छ(प्–ड) नेतृत्व के लिए अपने कैडरों को वापस जंगलों में भेजने का आदेश देना मुश्किल होगा। अब नागा शांति सूत्रधार क्या कर सकते हैं? खैर, सबसे बड़ा सूत्रधार मुख्यमंत्री रियो के नेतृत्व वाली नागालैंड सरकार है। वास्तव में, नागालैंड में पिछले कुछ समय से विपक्ष–रहित सरकार है और विपक्ष न होने का विचार नागा शांति प्रक्रिया को एक स्वर में आगे बढ़ाना है। नागालैंड सरकार ने नागा मुद्दे पर एक राजनीतिक मामलों की समिति गठित की है और इस समिति ने राजनीतिक स्तर पर एक नए वार्ताकार की नियुक्ति की सिफारिश की है, जो संभवतः एक केंद्रीय मंत्री हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में, श्री रियो और उनकी टीम ने एक बार फिर नई दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान अमित शाह के समक्ष यह मांग रखी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने जाहिर तौर पर टीम रियो से कहा कि वे एनएससीएन (आई–एम) को अलग झंडे और संविधान की अपनी मांग पर पुनर्विचार करने के लिए कहें। इस पृष्ठभूमि में, नागा बंधन निश्चित रूप से जारी रहेगा।

बांग्लादेश से बिगड़ते रिश्तों के यक्ष प्रश्न

पुष्परंजन

आपको चिटगांव जाना हो, तो सबसे शॉर्टकट रास्ता त्रिपुरा होकर है। गत 9 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री मोदी, और उनकी तत्कालीन समकक्ष शेख हसीना ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था। दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम कस्बे से मैत्री सेतु के बरास्ते सीमा पार कीजिये, और रामपुर पहुंच जाइये, जो चिटगांव का उपजिला है। मैत्री सेतु अब भी चालू है, लेकिन सीमा आर–पार से 'मैत्री' गायब है। बुधवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, सनातनी हिंदू सेना ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी को 'अस्वीकार्य' बताया, और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया, कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों और इस्कॉन पर बार–बार होने वाले हमलों के लिए जिम्मेदार है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, 'यह बर्बरता है। इस्कॉन ने बांग्लादेश में आपदा राहत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी उस पर हमला हो रहा है।' बांग्लादेश में जो कुछ इस समय हो रहा है, चिटगांव उसका अधिकेंद्र है। इसे एपीसेंटर बनाने में चिन्मय कृष्ण का बड़ा हाथ है। अपने धुआंधार धार्मिक भाषणों के लिए जाने जाने वाले चिन्मय कृष्ण, चिटगांव के सतकानिया उपजिला से हैं। उनके तीन नाम हैं, 'चंदन कुमार धर प्रकाश', 'चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी', और तीसरा नाम है, 'शिशु बोक्ता'। उन्होंने कम उम्र से ही धार्मिक उपदेशक के रूप में अपनी लोकप्रियता के कारण 'शिशु बोक्ता' उपनाम अर्जित किया था। 2016 से 2022 तक, उन्होंने इस्कॉन के चिटगांव मंडल सचिव के रूप में कार्य किया। फिर, 2007 में चिन्मय कृष्ण, चिटगांव के हथजारी में पुंडरीक धाम के प्रधान बनाये गये। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्कॉन बांग्लादेश ने स्पष्ट किया, कि चिन्मय कृष्ण दास (जिनकी गिरफ्तारी के कारण हाल ही में अशांति फैली), लीलराज गौर दास, और स्वतंत्र गौरांग दास सहित कुछ व्यक्तियों को पहले ही नियमों का उल्लंघन करने के कारण संगठन से हटा दिया गया था। इस्कॉन के महासचिव चारुचंद्र दास ने स्पष्ट किया कि उनकी कार्यशैली व्यक्तिगत थीं, और उनका इस्कॉन से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा, 'इस्कॉन बांग्लादेश कभी भी सांप्रदायिक या संघर्ष–प्रेरित गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। इस्कॉन, एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना जारी रखेगा।' देशव्यापी अशांति के बीच अगस्त, 2024 में 'सनातन जागरण मंच' का उदय हुआ। चिन्मय दास को इसका प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। इस्कॉन का प्रतिनिधित्व करने की बजाय, चिन्मय कृष्ण बांग्लादेश के व्यापक हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने लगे। प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर चली गईं, तो बड़े पैमाने पर विद्रोह के दौरान कई हिंदू घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसके जवाब में, यह मंच शुरू किया गया। हाल ही में सनातन जागरण मंच ने चिटगांव और रंगपुर में बड़ी रैलियां आयोजित कीं, जहां चिन्मय ने हिंदू समुदाय के अधिकारों की वकालत करते हुए जोशीले भाषण दिये थे। लेकिन क्या, 'सनातन जागरण मंच' के गठन, और उसे मिलने वाले फंड के पीछे रॉ की कोई भूमिका है? ढाका के पावर कॉरिडोर से इस बात का इशारा बराबर हो रहा है, मगर 'ऑन द रिकार्ड' अबतक किसी अधिकारी ने बयान नहीं दिया है। 25 अक्तूबर, 2024 को चिटगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने के आरोप में चिन्मय और 18 अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला, 30 अक्तूबर को दर्ज किया गया था। इसी केस के सिलसिले में चिन्मय कृष्ण को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) ने 25 नवम्बर, सोमवार को शाम 4रू30 बजे हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया। मंगलवार को उन्हें चिटगांव की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चिन्मय कृष्ण को जेल भेजने का आदेश जैसे दिया, उनके अनुयायियों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिये। कोर्ट परिसर में ही बेकाबू भीड़ ने एक युवा वकील सैफुल इस्लाम आलिफ को पीट–पीट कर मार डाला था। हिंसक भीड़ को काबू करने के वास्ते पुलिस फायरिंग भी हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट परिसर में वकीलों के चेंबर, और एक मस्जिद में भी तोड़फोड़ की थी। उत्पात में कुल 26 लोग घायल हो गए। उधर, शेख हसीना की पार्टी के छह लोग गिरफ्तार किये गए हैं। वकील अपने साथी की मौत के सवाल पर सड़क पर हैं। अंतरिम सरकार इसमें बुरी फंसी है। यह दिलचस्प है, कि चिन्मय कृष्ण के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज करवाने वाले मोहम्मद फिरोज खान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट में हुई हिंसक घटना के बाद, मोहम्मद फिरोज खान को 'सुरक्षा के लिए पुलिस हिरासत' में रखा गया है। सीधी सी बात है, खालिदा जिया की पार्टी, 'बीएनपी' का एक प्यादा इस काण्ड में फंस चुका था। इसलिए, उसे दूध की मक्खी समझकर सस्पेंड किया गया। सबसे मुश्किल स्थिति भारत–बांग्लादेश के बीच आई तल्खी को लेकर है, जो शेख हसीना के निर्वासन के बाद से रुक नहीं पा रही। अभी हाल में विदेश मंत्रालय के कुछ डिप्लोमेट मिले। उन्होंने स्वीकार किया कि बांग्लादेश की कूटनीति को हैंडिल करना, आज की तारीख में सबसे चुनौती भरा काम है। भारतीय मीडिया की भूमिका भी इस समय संबंधों के लिहाज से सकारात्मक नहीं है। मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने सच्चाई को तोड़–मरोड़ कर पेश करने की वजह से भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया है। अब निशाने पर हैं उद्योगपति अडानी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने कहा कि समिति वर्तमान में सात प्रमुख ऊर्जा और बिजली परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है, जिसमें अडानी पावर का कोयला आधारित संयंत्र भी शामिल है। ढाका ट्रिब्यून ने आज के सम्पादकीय में लिखा, 'एक ऐसा देश जिसने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसकी हालिया आक्रामकता और अपनी सुविधा की सूचना देने की प्रवृत्ति हैरान करने वाली है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है, कि भारत ने बांग्लादेश के अंदरूनी मामले को ऐसे समय में उजागर किया है, जब उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। हालांकि, यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से जुड़े प्रश्न बांग्लादेशियों को पूछने चाहिए।

योगी कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल

लखनऊ,(संवाददाता)। विधान सभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन के 9 में से 7 सीट जीतने के बाद अब फिर से प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई विधायक जहां मंत्री बनने के लिए जोड़–तोड़ में जुट गए हैं, वहीं सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी करने की तैयारी में हैं। हालांकि, मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद संभव है। सूत्रों की मानें तो इस बार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। इनमें कई कैबिनेट और राज्यमंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है। उपचुनाव के पहले से ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की कयासबाजी शुरू हुई थी, लेकिन किसी न किसी कारण से यह मामला टलता रहा है। उपचुनाव निपटने के बाद सरकार और पार्टी के स्तर पर मिशन–2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार को अधिक दिन नहीं टाला जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में जल्द ही दिल्ली में बैठक होगी। इसमें विस्तार की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके बाद विस्तार को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ओबीसी और दलित मतदाताओं के बिखराव से भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसकी भरपाई उपचुनाव में करने के लिए सरकार और संगठन ने कड़ी मेहनत की थी। इसका सार्थक परिणाम भी सामने आया है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी और दलित समीकरण साधने के लिहाज से चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि उपचुनाव में जीतने वाले एक या दो विधायकों को भी मौका दिया जा सकता है। खास तौर से दशकों से जिन सीटों पर भाजपा नहीं जीती थी, वहां से जीतने वाले विधायकों को मंत्रीपद देकर पुरस्कृत किया जा सकता है। वहीं, लंबे समय से मंत्री रहने के बावजूद बेहतर परिणाम न देने वाले कई मंत्रियों को बाहर भी किया जा

सकता है। ऐसे कई मंत्रियों की कार्यप्रणाली का आकलन किया जा रहा है। संगठन में बेहतर काम करने वालों खासतौर से उपचुनावों की रणनीति में जुटने वाले कुछ संगठन के नेता भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपचुनाव में सीट में भागीदारी से वंचित रह गए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जहां मंत्रिमंडल में एक और पद पाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मीरापुर सीट जीतने वाले रालोद भी दबाव बना सकता है। ऐसे में प्रस्तावित विस्तार में बड़े पैमाने पर फेरबदल संभव है।

निबंध प्रतियोगिता में अनुष्का ने प्रथम स्थान प्राप्त किया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

झबरेड़ा,हरिद्वार। भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम कसौली में निबंध प्रतियोगिता तथा खेलकूद में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय के प्राध्यापक ममता सिंह, मोहम्मद इकराम तथा वीर सिंह पवार ने उपस्थित होकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि ममता सिंह ने उपस्थित छात्र–छात्राओं को भारतीय संविधान के महत्व की जानकारी दी, वही मोहम्मद इकराम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने भारत संविधान का निर्माण कर भारत को विश्व के सामने बड़ी मजबूती से प्रस्तुत किया तथा वीर सिंह पवार ने उपस्थित छात्र–छात्राओं को अपनी ओर से ढेर आशीर्वाद दिया मंच पर मंजू बाला तथा सुशील कुमार विक्रम सिंह ने उपस्थित होकर अपना सहयोग दिया इस अवसर पर समाजसेवी दीपक मौर्य ने मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण करके किया। निबंध प्रतियोगिता में अनुष्का ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर बालिकाओं के कबड्डी प्रतियोगिता में मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स अकादमी ने सूर्या अकैडमी को 18 के मुकाबले 13 अंकों से हराकर विजेता बनी। यह आयोजन मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स अकैडमी के संरक्षण में संपन्न हुआ जिसको सफलतापूर्वक अब्दुल रहमान, मोहित, अंकुल चौहान, आंचल, प्रियांशु एवं अन्य खेल प्रेमियों ने उपस्थित होकर संपन्न कराया।

किसी को भाई भटकने के लिए छोड़ गया तो किसी को पुलिस, इंतजार है इनको

अलीगढ़,(संवाददाता)। ढाई साल पहले भाई रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया। समझ नहीं आ रहा था कहां जाऊं। इधर–उधर भटक रही थी तो पुलिस वाले वृद्धाश्रम छोड़ गए। तब से आज तक किसी ने सुध नहीं ली। यह बताते हुए कमालपुर निवासी 58 वर्षीय नजमा सिद्दीकी का गला रुंध गया और वह रोने लगीं। कुछ ऐसी ही अनकही कहानियां हैं शहर के वृद्धाश्रमों में रह रहे वृद्धजनों की... किसी को घर वालों ने निकाल दिया है तो किसी का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। पड़ोसियों–रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया। जब शरीर ने साथ छोड़ दिया और बीमारियों ने जकड़ लिया तो वृद्धाश्रम उनके बुढ़ापे का सहारा बन गया। दाऊजी सेवाधाम वृद्धाश्रम में रह रहे अलीगढ़ निवासी 68 वर्षीय भूषण बन्ना की कहानी भी कुछ ऐसी है। भूषण बन्ना मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ हैं। वे कोई काम नहीं करते थे। पत्नी टीचर है। पत्नी ने यह कहते हुए घर से निकाल दिया कि कोई काम नहीं करते हो। ऊपर से बैठकर हमारी कमाई खाते हो। यहां रहोगे तो बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब से आज तक वह वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं।

मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो........ भजन सुनकर झूम उठे श्रोता

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। कर्मयोग जनकल्याण समिति द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन भगवत नाम के प्रसाद का रसपान करते श्रोता गण, प्रियदर्शिनी कालोनी सीतापुर रोड स्थित भागवत पार्क में श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन आचार्य संतोष भाई जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को इंद्र का अभिमान तोड़ना था। उनकी ओजस्वी वाणी से सभी सहमत हो गए और इंद्र देव भगवान श्रीकृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज पर्वत के ऊपर दूसरे विशाल रूप में प्रकट हो गये और उनकी सामग्री खाने लगे यह देख सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो गए. जब अभिमानी इन्द्र को पता लगा कि ब्रजवासी मेरी पूजा को बंद करके किसी पर्वत को पूज रहे हैं, तो वह बहुत क्रोधित हुए. तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों को ब्रज पर मूसलाधार पानी बरसाने की आज्ञा दी. इन्द्र देव को अभिमान था। इस अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर प्रजा और वनस्पति को बचा लिया। भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं हमारी इंद्रियां गाय का स्वरुप है इंद्रियों का चरवाहा भगवान श्रीकृष्ण को बना देना ताकि इंद्रियां विषयों में रमण ना करें भगवान के चरणों में सभी इंद्रियों को समर्पित कर देना चाहिए गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है गोपी एक भाव है जो पुरुष और स्त्री दोनों धारण कर सकते हैं गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर कात्यानी मैया की पूजा की भगवान ने सब गोपियों को ज्ञान देकर अपनी शरणागत प्रदान की भगवान श्री कृष्ण ने रास विहार के द्वारा देह भाव से ऊपर उठने की भक्ति बताई जीव और शिव का मिलन है कंस के अत्याचारों से पाप बढ़ने लगे नारद जी के समझाने पर भगवान श्री कृष्ण कंस का उद्धार करने मथुरा गए कंस अभिमान का प्रतीक है और अभिमानी का नष्ट हो जाना ही उसकी गति है अभिमान को त्याग देना चाहिए काम एवं क्रोधा से ज्यादा अभिमान जीवन में घातक है। भगवान ने अपने जीवन काल में सांदीपनि ऋषि के पास शिक्षा दीक्षा प्राप्त की भगवान के अनन्य सखा उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था। भगवान कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी से कहा, उद्धव जी ने गोपियों को जब समझाया तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण प्रेम के आगे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हम तो कृष्ण के प्रेम में ही मगन है। गोपियों ने उनको भक्ति की कंठी पहना कर वापस कर दिया।ऊधो ने भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त की और ज्ञान का प्रचार किया।भगवान ने जरासंध का उद्धार किया जरासंध जरासंध को जरासंध को जरासंध को जरासंध को जरासंध को आचार्य जरासंध को आचार्य जी ने जरासंध को आचार्य जी ने जरासंध को आचार्य जी ने जरासंध को आचार्य जी ने जरासंध को आचार्य जी ने वृद्धा जरासंध को आचार्य जी ने वृद्धा अवस्था का रोग बताया जरासंध को आचार्य ने वृद्धा अवस्था का रोग बताया भगवान ने द्वारिका मे सेवा का कार्य करते हुए समाज की सेवा की मां रुकमणी की प्रार्थना पर नारद जी ने रुकमणी को भगवन द्वारिकाधीश के गुणों के बारे में बताया कालान्तर में द्वारिकाधीश ने रुक्मणी का हरण कर के उनसे विवाह रचाया रुक्मणी मंगल के अवसर पर भव्य झांकी बनाई गई रामासरे जी की भजन मंडली ने सुन्दर भजन प्रस्तुत किये आओ मेरी सखियो मुझे मेहदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो इस भजन पर सभी भक्तों ने खूब नृत्य किया । इस अवसर पर कथा मे प्रेम नारायण व्यास जी ,धर्म देव सिंह,निर्देश दीक्षित,राम कुमार सिंह ,श्याम सुन्दर शर्मा,नंदलाल गुप्ता, सिंह वीर सिंह,जितेन्द्र सिंह ,अजीत सोनी संजय सिंह,इंद्र प्रकाशजी,उमा प्रसाद पांडे,सुशील मोहन शर्मा,मुदित ,तनय सोनी,अथर्व राज मिश्रा,अनुज शुक्ला,रेखा श्रीवास्तव,निर्मला वर्मा ऋचा सचान आदि बहुत बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवत नाम रस का रसास्वादन कर कथा का श्रवण किया।

आरएआईटीबी-एनएफएल सम्मेलन के प्रथम दिवस को व्यापार पर एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आईआईएलएम अकादमी ऑफ हायर लर्निंग, लखनऊ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और विलफ्रिड लॉरियर विश्वविद्यालय (डब्लूएलयू), कनाडा के सहयोग से ''व्यापार को बदलने में एआई की भूमिकारू भविष्य के परिदृश्य को नेविगेट करना (आरएआईटीबी–एनएफएल)'' पर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन समारोह और आईआईएलएम छात्रों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई, जो ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज का प्रतीक है। आईआईएलएम लखनऊ में डीन अकादमिक और सम्मेलन की संरक्षक डॉ0 शीतल शर्मा ने स्वागत भाषण दिया और सम्मेलन का कॉन्सेप्ट नोट प्रस्तुत किया। उन्होंने 70 से अधिक उपस्थित लोगों की भागीदारी तथा भारत और विदेशों के विद्वानों द्वारा 34 शोध–पत्र प्रस्तुतियों पर प्रकाश डाला। डॉ0 शीतल ने मुख्य अतिथि प्रो0 आलोक कुमार राय (कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय), डॉ0 अकबर सईद (एसोसिएट प्रोफेसर, विलफ्रिड लॉरियर विश्वविद्यालय, कनाडा) और डॉ0 विभूति गुप्ता (प्रोफेसर, आईआईएलएम लखनऊ) सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके संबोधन में व्यवसायों

पर एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव, विभिन्न उद्योगों में इसके अनुप्रयोगों और इससे उत्पन्न चुनौतियों पर जोर दिया गया।

मुख्य भाषण की मुख्य बातें

डॉ0 अकबर सईद का मुख्य भाषणरू डॉ0 सईद ने ''एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रहरू एक सामाजिक–तकनीकी परिप्रेक्ष्य'' पर बात की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एआई एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह किस प्रकार सामाजिक असमानताओं को दोहरा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा महिलाओं को कम क्रेडिट सीमा प्रदान करने जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए, उन्होंने जवाबदेही, मूल्य संरेखण, व्याख्यात्मकता, निष्पक्षता और उपयोगकर्ता डेटा अधिकारों सहित ऐसे पूर्वाग्रहों से निपटने की रणनीतियों को रेखांकित किया। डॉ0 सईद ने निष्पक्ष एआई सिस्टम डिजाइन करने के लिए एक मॉडल भी प्रस्तुत किया, जिसमें नैतिक एआई अनुप्रयोगों को सुनिश्चित करने के लिए बहु–विषयक सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया।

डॉ0 विभूति गुप्ता का मुख्य भाषण

डॉ. विभूति ने ''एआई–सेवी लीडर और एआई–सेवी लीडरशिप'' पर चर्चा की, पुलिसिंग, कॉरपोरेट्स में एआई की भूमिका और तकनीकी और गैर–तकनीकी व्यवसाय के नेताओं के बीच एआई एकीकरण के प्रति दृष्टिकोण के अंतर पर अपने शोध से अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने अभिनव कानून प्रवर्तन प्रथाओं के लिए दुबई पुलिस द्वारा एआई के उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आत्मघाती प्रवृत्तियों की पहचान करने जैसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मेटा और यूपी पुलिस के बीच हाल ही में हुई साझेदारी को भी संबोधित किया। डॉ0 विभूति ने नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने में जनरेटिव एआई की भूमिका पर जोर दिया, नेताओं से प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए एआई को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने का आह्वान किया। डॉ0 सईद द्वारा सम्मेलन की कार्यवाही का अनावरण किया गया।

डॉ0 शीतल ने गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करके और मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ताओं को आभार प्रमाण पत्र प्रदान करके उद्घाटन सत्र का समापन किया।

तकनीकी सत्र–1 सारांश

पहले तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रो0 मनीषा सेठ (जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ) ने की और संचालन डॉ0 विभूति गुप्ता (आईआईएलएम लखनऊ) ने किया, जिसमें छह प्रभावशाली शोध पत्रों के माध्यम से ''प्रबंधन कार्यों में एआई के अनुप्रयोग'' विषय पर चर्चा की गई। प्रस्तुतकर्ताओं ने आईएफटीएम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, सेंट जेवियर्स कॉलेज (काठमांडू), जामिया हमदर्द (नई दिल्ली), एमसीएनयूजेसी भोपाल और आईआईएलएम लखनऊ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया। अध्ययनों ने बैंकिंग, भर्ती, विपणन, मानव संसाधन, वित्तीय साक्षरता और ब्रांडिंग में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर गहन चर्चा की। विषयों में विलय के बाद बैंकिंग दक्षता में एआई की भूमिका, एआई–संचालित भर्ती की पूर्वाग्रह को कम करने की क्षमता, उपभोक्ता विश्वास बनाने के लिए एआई के माध्यम से विपणन का निजीकरण और कार्यबल अनुकूलन के लिए मानव संसाधन में इसका उपयोग शामिल थे। अन्य प्रस्तुतियों में रोबो–सलाहकारों जैसे उपकरणों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता में सुधार करने में एआई के योगदान और चौटबॉट और व्यक्तिगत सामग्री के माध्यम से ब्रांड धारणा पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई। दक्षता में सुधार, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने में एआई के लाभों पर जोर देते हुए, चर्चाओं ने एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह, नैतिक चिंताओं और पारदर्शिता के महत्व जैसी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। सत्र का समापन अध्यक्ष से मूल्यवान प्रतिक्रिया के साथ हुआ, जिसने उद्योगों में एआई के एकीकरण के आगे के अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। आरएआईटीबी–एनएफएल सम्मेलन के प्रथम दिवस ने उद्योगों को नया रूप देने में एआई की भूमिका पर सार्थक चर्चाओं और अभूतपूर्व शोध को मिलाकर एक आशाजनक स्वर स्थापित किया। इस कार्यक्रम ने नैतिक और अभिनव एआई समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित किया, स्थायी व्यावसायिक परिवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी अंतर्दृष्टि को बढ़ावा दिया।

छात्राओं को उनके अधिकार बताकर किया जागरूक

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। थाना जानकीपुरम क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम नगर में जाकर मिशन शक्ति अभियान फेज–5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, अधिकारों और उन्हें उपलब्ध सेवाओं व साइबर फ्राड व साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर थाना जानकीपुरम में नियुक्त म0उ0नि0 शिवानी वर्मा ,व अन्य कर्मचारीगण द्वारा स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना, सुरक्षा के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं और यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सेवाओं की जानकारी देना था। इस दौरान महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की गईं, जैसे कि

1090 महिला हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सेवा और महिला पावर लाइन जैसी सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना है।

भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबन्ध निदेशक (मानव संसाधन) एवं सीडीओ का लखनऊ दौरा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबन्ध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉर्पोरेट विकास अधिकारी, श्री बिनोद कुमार मिश्रा ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत आस्था नव चेतना फाउंडेशन (एनजीओ), लखनऊ को उत्तर प्रदेश के नौ जिलों में कुल 50 सरकारी कॉलेजों में सेनेटरी पैड इन्सिंनरेटर एवं वेंडिग मशीनें स्थापित करने हेतु रु 20.60 लाख का चेक भेंट किया। उप प्रबन्धा निदेशक श्री बिनोद कुमार मिश्रा जी ने अपने सम्बोधन मे कहा कि यह भेंट भारतीय स्टेट बैंक की ओर

से भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एक विनम्र अंशदान स्वरूप है। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), श्री राजीव कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक, लखनऊ मण्डल, श्री शरद स चांडक, महाप्रबंधकगण श्री अनिल कुमार, नेटवर्क–1, श्री एम.एल.वी. एस. प्रकाश, नेटवर्क–2 और श्री कौशलेन्द्र कुमार नेटवर्क–3 के साथ बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

नगर के युवक कार्तिकेय ने लंदन में शिक्षा क्षेत्र में बढाया मान

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

गोण्डा। जनपद मुख्यालय के निवासी पुंडरीक कुमार उर्फ राजा साहब के होनहार पुत्र कुमार कार्तिकेय को ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी आफ लंदन ने कंप्यूटर साइंस में साइबर सिक्योरिटी विषय पर एमटेक से सम्मानित किया गया है। मोहल्ला सुभाष नगर में 15 मई 2000 को जन्में कार्तिकेय की प्रारंभिक शिक्षा नगर के सैंट थॉमस पब्लिक स्कूल इंटर मीडिएट फातिमा कॉलेज व देहरादून यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम से 2020 में कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी में बीटेक की डिग्री प्राप्त किया। कॉलेज

से इनका कैंपस सिलेक्शन होने पर वर्ष 2022 तक मल्टी नेशनल कंपनी बीटी ब्रिटिश टेलीकॉम में प्रवेश लिया और 2024 में लंदन के प्रतिष्ठित किंग यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से साइबर सिक्योरिटी में मेरिट अंको के साथ एमटेक उपाधि प्राप्त किया। बर्मिंघम स्थित अपने आवास से दूरभाष पर वार्ता करते हुए कुमार कार्तिकेय ने अपने भविष्य की योजना पर चर्चा में बताया कि वह शीघ्र ही जर्मनी से पीएचडी में प्रवेश ले रहे हैं। नगर के मेधावी युवा की सफलता पर पूर्व सांसद कुंअर आनन्द सिंह, पूर्व विधायक रघुराज प्रसाद उपाध्याय, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह सूरज सिंह, राजीव रस्तोगी व शिवकुमार सोनी संतोष सोनी व शिवराज सिंह ने हर्ष व्यक्त किया है।

शहर को साफ–सुंदर बनाने के लिए सफाई मित्रों का सम्मान

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)

नगरपालिका परिषद पिहानी में शनिवार को साफ–सफाई में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सफाई मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने सम्मानित किया ।सम्मान समारोह में वार्ड के उन सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया गया, जो दिन रात शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटे हुए हैं। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि शहर को सुंदर, साफ व स्वच्छ बनाने में निगम के सफाई कर्मचारियों को अहम योगदान है। इन्हें हम अगर सफाई कर्मचारी की जगह सफाई मित्र कहकर संबोधित करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी एक तरह से हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। जब हम रात को चौन की नींद ले रहे होते हैं तब हमारे ये सफाई मित्र रात के अंधेरे में भी सड़कों को साफ करते नजर आते हैं। नगर पालिका के गोपाल कृष्ण अवस्थी ने कहा कि हम स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। इसके लिए हमारे ये सफाई मित्र शहर को साफ व स्वच्छ बनाकर स्वच्छ वातावरण बनाने में अहम भूमिका निभाते है। हमें भी शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मुख्य सफाई निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि नगर निगम द्वारा अमृत महोत्सव के तहत हर वार्ड के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। हर वार्ड का सभासदवहां सफाई करने वाले कर्मचारियो का सम्मान कर रहा है। इस मौके पर सभासद प्रतिनिधि अरुण गुप्ता ,संजय कुशवाहा ,अश्विनी बाजपेई ,अरुण अग्निहोत्री ,अशोक कुमार आदि लोग मौजूद रहे।

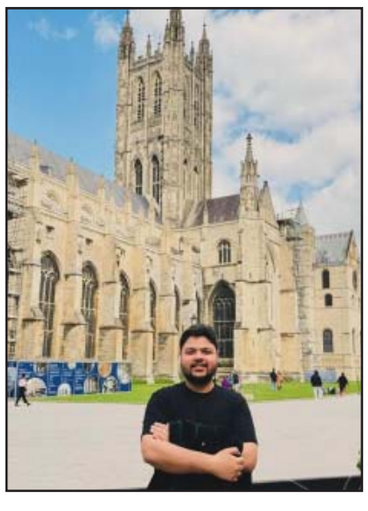

खाक चौक पर भूमि को लेकर साधु संतों ने मेला प्राधिकरण कार्यालय पर किया प्रदर्शन

प्रयागराज़,(संवाददाता)। खाक चौक व्यवस्था समिति के साधु संतों ने शुक्रवार को मेला प्राधिकरण कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। संतोष दास सतुआ बाबा समेत बड़ी संख्या में संत सुबह ही सैकड़ों साधु और संन्यासियों के साथ दारागंज स्थित मेला प्राधिकरण कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया कि मेला प्रशासन खाक चौक की भूमि को दूसरों क आवंटित कर रहा है। इसी तरह महामंडलेश्वर स्वामी रामतीर्थ दास ने भी मेला प्रशासन पर भूमि आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 1965 से पूर्व खाक चौक के संतों को जमीन आवंटन संगम के पास हो रहा था, लेकिन 2019 के कुंभ से मेला प्रशासन जमीन आवंटन में गड़बड़ी कर रहा है। उन्होंने बताया कि मेला प्रशासन के अफसरों ने खाक चौक के संतों को देश के कोने–कोने से जमीन आवंटन के लिए बुला लिया है,। लेकिन जमीन आवंटन में गड़बड़ी की जा रही है। इससे संतों में आक्रोश है।

एम.एड. पाठ्यक्रम में द्वितीय काउंसिलिंग 9 दिसंबर को

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में एम.एड. पाठ्यक्रम (सत्र 2024–26) में प्रवेश के लिए द्वितीय काउंसिलिंग 9 दिसंबर 2024 को सुबह 10रू30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के विश्वश्वरैया हाल, यू.एन.एस. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित की जाएगी। सामान्य रैंक 001 से 433 तक के अभ्यर्थी, जिन्होंने अब तक प्रवेश नहीं लिया है, इस काउंसिलिंग में शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थी अपना काउंसिलिंग पत्र 2 दिसंबर 2024 से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ‚अइेचनण्बण्पद से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रारूप ष्कष् एवं ष्खष् विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर उन्हें पूर्ण रूप से भरकर, काउंसिलिंग हेतु जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना होगा। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।

संक्षिप्त खबरें

चंद घंटे में पैरा शूटर को बनाकर दिया पासपोर्ट

लखनऊ,(संवाददाता)। एक पैरा शूटर ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, लेकिन पेमेंट न होने से प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसलिए वह क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे। इस पर अफसरों ने कुछ ही घंटे में पासपोर्ट बनाकर दिया। इससे अब वह दुबई में होने वाली चौंपियनशिप में शिरकत कर सकेंगे। कृष्ण कांत सिंह पैरा शूटर हैं। उन्होंने बताया दुबई में पैरा शूटिंग की विश्व चौंपियनशिप होने वाली है। इसके लिए 2 से 10 दिसंबर के बीच दिल्ली में ट्रायल है। उन्होंने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया तो पेमेंट फंस गया। पासपोर्ट कार्यालय पहुंच आरपीओ शुभम सिंह को पूरा मामला बताया। दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन कर अफसरों ने चंद घंटों में प्रक्रिया पूरी की। पुलिस सत्यापन करवाकर रिपोर्ट मंगवाई और फिर पासपोर्ट बनाकर कृष्णकांत को सौंपा।

लगातार आ रहा है बुखार तो फौरन डॉक्टर से मिलें

लखनऊ,(संवाददाता)। दो–तीन दिन से ज्यादा आ रहा है बुखार तो बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। फौरन डॉक्टर से परामर्श लेकर ब्लड टेस्ट कराएं। अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से मटियारी चौराहे पर लगे स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टरों ने मरीजों को यह जानकारी दी। शिविर में 79 लोगों ने सेहत की जांच करवाई। शिविर में सबसे ज्यादा 48 लोगों की सीबीसी जांच की गई। साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लडग्रुप आदि की भी जांच की गई। डॉक्टरों ने बताया कि 48 लोगों का ब्लड प्रेशर, 19 लोगों की शुगर, 48 लोगों की एसपीओटू (ऑक्सीजन संतृप्ति), 5 लोगों के ब्लड ग्रुप की जांच की गई। कुछ ने वजन व हाइट भी चेक करवाया। सीएमओ की मेडिकल वैन टीम से डॉ. सोमेंद्र रस्तोगी, फार्मासिस्ट मनीष पाल, स्टाफ नर्स नितिन श्रीवास्तव, लैब टेक्नीशियन सौरभ श्रीवास्तव आदि ने लोगों की जांच की। आयोजन ट्रांस गोमती आदर्श व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में हुआ। सहयोगी में स्थानीय निवासी व व्यापारी फहीम, आदिल, मनजीत, अमित कुमार, राजेश, अकील, पप्पू रावत व अखिलेश दुबे का योगदान रहा।

690 दिव्यांगों को मिलेंगे कृत्रिम हाथ–पैर

लखनऊ,(संवाददाता)। सड़क हादसे या किसी बीमारी के कारण दिव्यांगता का शिकार हुए 690 लोगों को कृत्रिम हाथ–पैर दिए जाएंगे। उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान की ओर से एक दिसंबर को निशुल्क नारायण लिम्ब एवं कैलीपर्स फिटमेंट शिविर लगेगा। संस्थान के ट्रस्टी एवं निदेशक देवेंद्र चौबीसा ने चारबाग बस स्टैंड स्थित होटल में बताया कि शिविर का आयोजन विभूतिखंड किसान बाजार स्थित दयाल गेटवे होटल में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। नारायण सेवा ने श्श्श्कुआं प्यासे के पासश्श्श योजना के तहत 28 जुलाई को निशुल्क नारायण लिंब मेजरमेंट कैंप लगाया था। इसमें 1260 रोगी आए थे। 690 लोग ऐसे थे जो दिव्यांगता का शिकार हो गए थे। अब इन्हें निशुल्क कृत्रिम हाथ–पैर दिए जाएंगे। संस्थान के मीडिया एवं जनसंपर्क निदेशक भगवान प्रसाद गौड़ ने बताया कि शिविर के उद्घाटन के लिए उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। 100 कृत्रिम हाथ–पैर का सहयोग टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सीएसआर मद से दिया है।

मोहनलालगंज में पकड़ा गया अवैध खनन, एफआईआर

लखनऊ,(संवाददाता)। मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर एसडीएम व खनन अधिकारी की टीम ने जांच की। मामला सही मिलने पर खनन अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक ग्राम कुढ़ा में मिट्टी के अवैध खनन की शिकायत बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। टीम जांच करने पहुंची। जांच में पाया गया कि कुढ़ा गांव में कुल 5000 घन मीटर साधारण मिट्टी खनन की अनुज्ञा मेसर्स श्री श्याम इंटरप्राइजेज के पक्ष में स्वीकृत है। संबंधित की ओर से स्वीकृत मात्रा 5000 घनमीटर के सापेक्ष 3841.3 ही साधारण मिट्टी खनन किया गया है, जो मानक के अनुरूप है। जांच में पाया गया कि इस खनन अनुमति से अलग ग्राम कुढ़ा में ही नन्हेराम व छेदालाल के नाम पर दर्ज जमीन पर खनन हो रहा है। मौके पर खनन बंद पाया गया। पूछताछ में लोगों ने बताया कि मिट्टी खनन का काम मनोज यादव नाम के व्यक्ति की ओर से ईंट–भट्टे परमीशन के नाम पर किया गया है। हालांकि, उक्त खनन के संबंध में कोई कागज नहीं दिखाया जा सका। जांच में खनन अवैध मिलने पर उप्र उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।

हत्या और साक्ष्य मिटाने के दोषी को उम्रकैद

लखनऊ,(संवाददाता)। युवक को घर से बुलाकर हत्या करने और ग्राइंडर से शव के छोटे–छोटे टुकड़े कर साक्ष्य मिटाने वाले अंशु सोनी को एडीजे अभिनय कुमार मिश्रा ने उम्रकैद की सजा सुनवाई है। सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले की रिपोर्ट वादी श्याम सुंदर ने 19 मई 2018 को पारा थाने में दर्ज कराई थी 18 मई को जब वादी दुकान से लौटा तो पाया कि बेटा राजकुमार घर पर नहीं था। पूछताछ में पता चला कि राजकुमार अपने दोस्त अंशु सोनी के साथ गया है। काफी तलाश करने पर राजकुमार का कुछ पता नहीं चल सका। अगले दिन सुबह वादी को जानकारी मिली कि बोरे में किसी की लाश मिली है। वादी मौके पर गया तो शव उसके बेटे का था। विवेचना के दौरान पता चला कि अंशु सोनी ने साथी वीरेंद्र यादव के साथ मिलकर राजकुमार की हत्या की। ग्राइंडर से शव के टुकड़े कर बोरे में भरकर फेंक दिए थे। वीरेंद्र की मौत हो चुकी है।

चिनहट पहुंचनी थी बरात, दूल्हा हुआ गुमशुदा

लखनऊ,(संवाददाता)। वजीरगंज में बृहस्पतिवार को बरात निकलने से पहले दूल्हा लापता हो गया। तय समय बीतने पर जब बरात चिनहट नहीं पहुंची तो लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को फोन किया तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। दूल्हे के पिता ने वजीरगंज थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई है। वजीरगंज स्थित एक घर से बृहस्पतिवार रात बरात चिनहट स्थित गेस्ट हाउस पहुंचनी थी। लड़की पक्ष के लोग बरात के स्वागत में जुटे थे। तैयारियां चल रही थीं। काफी रात होने पर जब बरात नहीं पहुंची तो लड़की वालों ने लड़के के पिता को फोन किया। दूल्हे के पिता ने बताया कि बेटा दोपहर में खरीदारी करने निकला था।

63 हजार निजी स्कूलों की छह लाख सीटों पर गरीब बच्चों का होगा प्रवेश, आरटीई के तहत होंगे रजिस्ट्रेशन

लखनऊ,(संवाददाता)। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू हो रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार स्कूलों व सीटों की संख्या बढ़ी है। 2025–26 में 62871 हजार निजी स्कूलों की छह लाख सीटों पर प्रवेश होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों का पुराना बकाया भुगतान होने के बाद इसमें निजी स्कूल भी रुचि ले रहे हैं। यही वजह है कि नए सत्र में आरटीई के लिए विभाग की ओर से 62871 स्कूल मैप किए जा चुके हैं। वहीं इसमें से 62829 स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी तरह कक्षा एक में 391130 व प्री प्राइमरी में 211935 सीट पर प्रवेश लिए जाएंगे। पिछले साल लगभग 3.57 लाख आवेदन हुए थे। इस बार विभाग पांच गुना आवेदन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। उप शिक्षा निदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस बार आवेदन के लिए प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग के कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। अगर किसी अभिभावक को आवेदन करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो वह यहां आवेदन निरूशुल्क करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार दिसंबर से ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है जो चार चरणों में मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। कक्षा एक में आगरा में सर्वाधिक 12608, जौनपुर में 12295, आजमगढ़ में 11795, बरेली में 10689, प्रयागराज में 9629, फिरोजाबाद में 9007, मुजफ्फरनगर में 9096, गाजीपुर में 8652, गोंडा में 8279 सीटें हैं। वहीं प्री प्राइमरी में लखनऊ में सर्वाधिक 23889, गोरखपुर में 9853, गाजियाबाद में 8333, वाराणसी में 8259, गौतमबुद्ध नगर में 8176, कानपुर नगर में 7429 सीटें हैं।

कब्जा लेने पहुंची एलडीए की टीम से किसानों की झड़प

लखनऊ,(संवाददाता)। एलडीए की मोहान रोड योजना के तहत कालिया खेड़ा गांव की अधिग्रहित जमीन पर कब्जा करने बृहस्पतिवार को पहुंची एलडीए की टीम व किसानों से जमकर झड़प हुई। झड़प होने से कई महिलाएं व ग्रामीणों घायल हो गए। किसानों के न मानने पर पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया। इस पर आक्रोशित किसानों ने कालिया खेड़ा रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मोहान रोड योजना के तहत कालिया खेड़ा गांव की जमीन अधिग्रहित की गई। बृहस्पतिवार को एलडीए की टीम जमीन पर कई जेसीबी लेकर कब्जा लेने पहुंची। इस पर ग्रामीणों व एलडीए की टीम से झड़प हो गई। पुलिस ने किसानों को समझाकर शांत कराया। आक्रोशित किसान कालिया खेड़ा रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता मनीष यादव व विनोद साहू, राम सहाय यादव आदि ने बताया कि आबादी, पेड़ पौधों, कुआं समेत अन्य का न तो सर्वे हुआ है और न ही मुआवजा तय हुआ। कुछ दिन पूर्व किसानों व एलडीए टीम के बीच हुई पंचायत में यह तय हुआ था कि 30 अक्तूबर को बातकर काम किया जाएगा। किसान नेता मनीष यादव ने कहा, पंचायत की बात हुए बिना एलडीए टीम बिना सूचना के गांव में कब्जा करने पहुंच गई। जो गलत है। देर शाम किसानों व एलडीए टीम के साथ बातचीत शुरू हुई। इसमे किसानों को सर्वे की गए घरों की सूची उपलब्ध कराई गई। किसानों ने आरोप लगाया कि एलडीए के अर्जन अधिकारी शशि भूषण पाठक अभद्रता की व मारपीट की। इसमें कई महिलाओं व ग्रामीणों को चोट आई है। चोटिल रीता ने बताया कि खेतों में फसल की बोआई हो चुकी थी, जिस पर एलडीए के अफसरों ने जेसीबी चलवा दी। संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह के साथ बातचीत तय हुआ था कि 30 नवंबर को बातचीत करने के बाद काम शुरू किया जाएगा।

बिल पास करने के लिए 10 फीसदी घूस मांगता है बाबू

लखनऊ,(संवाददाता)। साहब, बाबू (लिपिक) चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के लिए 10 फीसदी घूस मांग रहा है। मना किया तो कई माह से बिल अटकाए है और दौड़ा रहा है। कई बार हाथ भी जोड़े, जब बात नहीं बनी तो आपके दफ्तर में आकर शिकायत की है। ये दर्द कृषि विभाग में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुके शरद कुमार श्रीवास्तव ने सीएमओ ऑफिस में सीएमओ से बयां किया। सीएमओ ने शिकायत सुनने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही बाबू पुरुषोत्तम पांडेय से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का काम भी हटा लिया है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद बाबू पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बृहस्पतिवार दोपहर को शरद कुमार सीएमओ कार्यालय पहुंचे।

नई शिक्षा नीति संस्कार युक्त,तकनीक युक्तऔर रोजगार युक्तहै : रजनी तिवारी

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

सनातन धर्म इंटर कालेज में उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ के जनपदीय सम्मेलन में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि भारत की नई शिक्षा नीति 2020 भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई।नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव का उद्देश्य रखती है। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार आधुनिक और समावेशी बनाना है। नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद पिछली शिक्षा नीति (1986) को संशोधित कर लागू की गई है।स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश के लिए संस्कारयुक्त शिक्षा होनी चाहिए।नई शिक्षा नीति संस्कार युक्त, तकनीक युक्त और रोजगार युक्त है।जिससे हमारे नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगारपरक कौशल और वैश्विक मानकों के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली को तैयार करना है। इससे भारत को ष्ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाष् बनाने में मदद मिलेगी। मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चे कच्चे घड़े के रूप में अपलोग जैसा डालेंगे वैसे ढलेगे आप लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी है मां प्रधानमंत्री जी भी बीच बीच में छात्रों से संवाद करते रहते हैं जनपदीय सम्मेलन का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर प्रांतीय महामंत्री आशीष कुमार सिंह, मंडलीय अध्यक्ष विधानचंद्र द्विदी,प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मित्तल (राष्ट्रपति पुरस्कृत) पूर्व प्रधानाचार्य तुलसी राम कनौजिया आदि उपस्थित रहे। गंगा देवी के छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया।नई शिक्षा नीति पर गीता शुक्ला, पूर्व प्राचार्य सी एस एन कालेज वी एस पाण्डेय, तिलक राम यादव आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संघ की तरफ से सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर विशिष्ट अतिथि जिलाविदयालय निरीक्षक बालमुकुंद प्रसाद की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। आर्य कन्या की छात्राओं ने लोकनृत्य तथा एस डी कालेज के छात्र मोनू ने शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक सत्यम दीक्षित ने किया।सम्मेलन के सफल आयोजन में जिला मंत्री आलोक सिंह प्रवक्ता राजबीर सिंह अनिल अम्बेडकर वीरभानु सिंह, संदीप बाजपेई, अभिषेक अग्निहोत्री विंदु शेखर, दीप्ति सोनकर नीलम स्वतन्त्र आदि ने सहयोग किया।प्रधानाचार्य दिवाकर ने आये हुये अतिथियों का आभार व्यक्त किया।यहाँ उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को मैडल पहनाकर सम्मानित किया गया जिले के , 195 शिक्षक शिक्षिकायें उपस्थित रहे।संघ के कोषाध्यक्ष नीरज यादव वैशाली यादव सर्वेश शुक्ला महेंद्र वर्मा जिले प्रधानाचार्य के पी सिंह अमित समय सिंह सुनील रस्तोगी अरूण बाजपेई अभिराम सिंह सुशील शर्मा अजय शुक्ला आदि प्रधानाचार्य भी उपस्थित रहकर सभी का मनोबल बढ़ाते रहे। आज ही जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें जिलाध्यक्ष आलोक सिंह जिला मंत्री वीरभानु सिंह यादव, कोषाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, सत्यम दीक्षित प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, नीरज यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्व सम्मति से मनोनीत किया गया।

शार्ट सर्किट से बाइक एजेंसी में लगी भीषण आग

लखनऊ,(संवाददाता)। अमेठी के इंहोना में देर रात शॉर्ट सर्किट से हीरो बाइक एजेंसी में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पा लिया।आग से तीन बाइकें पूरी तरह से जलकर राख हो गईं जबकि कई अन्य बाइकें भी जल गईं। आग से एजेंसी मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इन्हौना थाना क्षेत्र के राजा फतेहपुर में फौजी हीरो बाइक एजेंसी है।

रक्तसंबंधों में विवाह से बच्चों में बढ़ रहीं दिमागी बीमारियां

लखनऊ,(संवाददाता)। बच्चों में विकसित होने वाली कई दिमागी बीमारियों की एक बड़ी वजह अपने ही रक्त संबंधों में विवाह है। ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, मिर्गी, सेरिब्रल पैल्सी, एडीएचडी जैसी बीमारियों की वजह से बच्चों का जीवन दूभर हो जाता है। उनके परिजनों को भी आजीवन तनाव और मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अमेरिका के पीट्सबर्ग विश्वविद्यालय से आए भारतवंशी वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उदयभान पांडेय ने आईआईटीआर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में बृहस्पतिवार को कहीं। उन्होंने कहा कि शोध में सामने आया है कि कुछ समुदायों में अपने ही रक्त संबंधों में विवाह (कांसैंगुनस मैरेज) के नतीजे में ऑटोसोमल रिसेसिव–जीन की वजह से पिछली पीढ़ियों की छिपी बीमारियां उभरकर सामने आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की पहचान व उपचार की दिशा में शोध और फंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग की दिशा में और बेहतर काम करने की जरूरत है। भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर) परिसर में बृहस्पतिवार को चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक कांफ्रेंस–अर्थ 2024 के दूसरे दिन अन्य कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने क्लाईमेट चेंज व पर्यावरण प्रदूषण से पैदा हो रहे खतरों और उनके समाधान पर मंथन किया। देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. डी. कानूनगो, अमेरिका केंटुकी से आए वैज्ञानिक डॉ. संजय श्रीवास्तव आदि ने भी यहां अपनी बात रखी।

संक्षिप्त खबरें

अगहनी जुमे की नमाज से समृद्धि की कामना, रोचक है इसका इतिहास

वाराणसी,(संवाददाता)। चार सौ 50 साल पहले, जब देश में सूखे ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, तब काशी के बुनकरों ने एक अद्वितीय प्रयास किया। उन्होंने पुरानेपुल पुलकोहना ईदगाह में अगहन महीने के जुमे में नमाज अदा की। इस नमाज की अदायगी के साथ ही, चमकीली बूंदें गिरीं और समृद्धि की किरणें फैलीं। आज भी यह परंपरा जारी है, जब हर साल अगहन माह के दूसरे जुमे को इस ईदगाह में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नमाज पढ़ी जाती है। इस नमाज में हजारों बुनकर एकत्रित होते हैं और आज के दिन मुर्री (कारोबार) भी बंद रहती है। यह परंपरा काशी के बुनकरों की एकता और समृद्धि की कामना का प्रतीक है। बुनकर तंजीम बाईसी के सरदार ने बताया कि अगहनी जुमे की नमाज अदा करने की परंपरा 450 साल से अधिक पुरानी है। यह परंपरा उस समय शुरू हुई जब देश में अकाल पड़ा और कारोबार ठप हो गए थे। लोग दाने–दाने को मोहताज हुए तो उस समय के लोगों ने इस ईदगाह में अगहनी जुमे की नमाज अदा की। उन्होंने बताया कि अल्लाह की बारगाह में बारिश और मुल्क की तरक्की के लिए हाथ बलंद किया तो उसने भी मायूस नहीं किया और जमकर बारिश हुई। तभी से यह परंपरा शुरू हुई और आज हम उसे निभाते आ रहे हैं। इस नमाज में बुनकर समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और तरक्की और समृद्धि की कामना की। अगहनी जुमे के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने कारोबार बंद रखे और नमाज अदा की। इसके बाद, सभी तंजीमों के सरदार और सदस्यों ने मिलकर बनारस के बुनकारी के कारोबार से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में कारोबार में हो रही दिक्कतों के बारे में चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक की खास बात यह रही कि इस बनारस में एक अनोखी परंपरा है, जहां हिन्दू और मुस्लिम मिलकर सभी त्योहार मनाते हैं। चाहे ईद हो, दिवाली हो या होली, सभी त्योहार एकता और सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं। आज का दिन भी इसी एकता का प्रतीक है, ।

प्लास्टिक कचरे से बने स्लीपर देंगे रेल ट्रैक को मजबूती

लखनऊ,(संवाददाता)। प्लास्टिक कचरे को फाइबर ग्लास मैटेरियल में बदला जा रहा है, जिससे रेलवे स्लीपर बनाए जा रहे हैं। ये बेहद मजबूत होने के साथ किफायती भी हैं। इससे खर्च घटेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। आरडीएसओ स्टेडियम में बृहस्पतिवार से शुरू हुई तीन दिवसीय इनो रेल प्रदर्शनी में शापोरजी पालोंजी कंपनी के स्टॉल पर इन रेलवे स्लीपरों को लगाया गया है। दरअसल, रेलवे स्लीपर पटरियों को जोड़ने का काम करते हैं। अभी रेलवे जिन स्लीपरों को इस्तेमाल करता है, वे कंक्रीट के बनते हैं, जिसमें काफी खर्च आता है। वहीं अब प्लास्टिक कचरे से स्लीपर बनाने का काम किया जा रहा

बेंच पर बैठे–बैठे गिरे रेलवे के सेक्शन इंजीनियर, मौत, परिजनों ने जांच की मांग की

लखनऊ,(संवाददाता)। रेलवे में सेक्शन इंजीनियर आनंद त्रिपाठी (58) की बुधवार देर रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बुधवार रात वह रामपुर जाने के लिए चारबाग स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे आनंद अचानक बैठे–बैठे गिर पड़े। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहराइच के नानपारा भलिया निवासी आनंद लखनऊ में गुडंबा के गायत्रीपुरम में परिवार के साथ रहते थे। वह रामपुर में तैनात थे। भाई अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि पिता मुकुट बिहारी त्रिपाठी का कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। उनकी तेरहवीं में शामिल होने के लिए आनंद रामपुर से लखनऊ आए थे। उधर, परिजनों ने ट्रेन की लोकेशन जानने के लिए आनंद को फोन मिलाया। काफी देर बाद एक अंजान व्यक्ति ने फोन उठाकर मामले की जानकारी दी। परिजन अस्पताल पहुंचे तो आनंद मृत मिले। उनके परिवार में पत्नी मधु त्रिपाठी और दो बेटे व दो बेटियां हैं।

उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले विधायकों ने ली शपथ : सीएम योगी

लखनऊ,(संवाददाता)। यूपी में नौ विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के वाले नवनिर्वाचित विधायकों को शुक्रवार को विधानसभा में शपथ दिलाई गई। सभी को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। इसके बाद भाजपा विधायक पार्टी कार्यालय पर पहुंचेंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे प्रदेश के विकास और जनता की आस्था की जीत बताया। जिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली उनमें कुंदरकी से रामवीर सिंह, फूलपुर से दीपक पटेल, खैर से सुरेंद्र सिंह, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, कटेहरी से धर्मराज निषाद, मझवां से सुचिस्मिता मौर्य और मीरापुर से रालोद की मिथलेश पाल शामिल हैं। इन सभी उम्मीदवारों ने जनता के विश्वास और समर्थन का धन्यवाद करते हुए अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। सभी ने एक स्वर में श्राष्ट्र प्रथमश के संकल्प को दोहराया, साथ ही मोदी–योगी के नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा जताई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य होना गौरव की बात है। जनता की सेवा का अवसर आपको मिला है। मुख्यमंत्री जी के कार्यों को लेकर अगर जनता के बीच में जाएं तो हर बार जीत आपको मिलेगी। आपके पास ढाई साल का समय है, उसे जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करें। इसके साथ ही आपकी उपस्थिति विधानसभा में भी दिखनी चाहिए। यहां आपकी परफॉर्मेंस ही जनता के बीच आपकी सक्रियता के संदेश के रूप में जाएगी। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई और भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मनमाना किराया नहीं ले सकेंगे ई रिक्शा वाले, अब प्रति किलो मीटर ले सकेंगे इतने रुपये

लखनऊ,(संवाददाता)। ई रिक्शा चालक अब यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। ये अधिकतम 8.30 रुपये प्रति किमी की दर से किराया ले सकेंगे। इसके लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने बृहस्पतिवार को इस बाबत पत्र जारी किया है। इसमें परिवहन आयुक्त व अन्य अफसरों को निर्देशित किया गया कि ठेका गाड़ी के रूप में चल रहे ई रिक्शा के किराये की अधिकतम दर प्रति किमी 8.30 रुपये तय की गई है। इस मार्च तक प्रदेश में तकरीबन पौने छह लाख ई रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं। अब इनकी संख्या बढ़ गई है। लखनऊ में 55 हजार पंजीकृत ई रिक्शा हैं। बगैर पंजीकरण के भी ई रिक्शा चल रहे हैं। लंबे समय से ऑटो रिक्शा की तरह इनके लिए भी किराया तय करने की मांग उठाई जा रही थी। यात्रियों की ओर से भी ई रिक्शा चालकों के मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें आ रही थीं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।